2012:CGHC:6172

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

खंडपीठ

कोरम : माननीय श्री यतीन्द्र सिंह, मुख्य न्यायाधीश और

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

---

1. **रिट याचिका संख्या 4520 सन् 2000**

याचिकाकर्ता : रतन कुमार जैन

बनाम

उत्तरवादीगण : मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़) और अन्य

तथा

2. **रिट याचिका (सी) संख्या 5354 सन् 2009**

याचिकाकर्ता : रतन कुमार जैन

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के

तहत रिट याचिकाएं

उपस्थित : याचिकाकर्ता, श्री रतन कुमार जैन, व्यक्ति रूप से उपस्थित हुए।

राज्य के महाधिवक्ता श्री संजय के. अग्रवाल ।

सुश्री फौजिया मिर्जा, सहायक सॉलिसिटर जनरल और श्री काशिफ शकील, भारत संघ के अधिवक्ता।

श्री जगदीप धनखड़, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ ग्रुप कैप्टन श्री करण सिंह भाट और श्री आर.के. गुप्ता, एसईसीएल के लिए अधिवक्ता।

श्री गौतम भादुड़ी, न्यायालय के मित्र के रूप में अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(5 दिसंबर, 2012)

1. 'हम पृथ्वी को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाते हैं, बल्कि इसे अपने बच्चों से उधार लेते हैं' एक पुरानी कहावत है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी माँ पृथ्वी को अपने बच्चों को कैसे वापस देते हैं। ये मामले, एक तरह से, उस कहावत की याद दिलाते हैं और निम्नलिखित अनुतोष के लिए हैं:

- रिट याचिका संख्या 4520 सन् 2000 (पहली रिट याचिका) दक्षिण पूर्व कोलफील्ड लिमिटेड (एसईसीएल) को आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध खनन करने, पेड़ काटने से रोकने और कोई कार्रवाई न करने वाले दोषियों पर मुकदमा चलाने के लिए है;

- रिट याचिका (सी) संख्या 5354 सन् 2009 (दूसरी रिट याचिका) अतिरिक्त कलेक्टर मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़) के दिनांक 22/8/2009 के राजस्व वाद संख्या 3ए-62/2006-2007 में पारित आदेश के विरुद्ध है, जिसमें एसईसीएल को पेड़ काटने की अनुमति के विरुद्ध श्री रतन कुमार जैन (याचिकाकर्ता) की आपत्ति खारिज कर दी गई थी।

तथ्य

2. चिरमिरी क्षेत्र में 1930 के दशक से कोयला खनन किया जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया और कोल इंडिया लिमिटेड (कोल-इंडिया) का गठन किया गया। इसे आगे विभाजित किया गया और एसईसीएल को कोल-इंडिया की सहायक कंपनी के रूप में गठित किया गया।

3. एसईसीएल छत्तीसगढ़ राज्य और मध्य प्रदेश राज्य में कोयला खनन में संलग्न है। यह चिरमिरी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ में भी कोयला निकालता है।

4. कोयला खदानें पूर्व कोयला निकालने के लिए पट्टों द्वारा दी गई थीं। राष्ट्रीयकरण के बाद, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएम अधिनियम) के तहत कोल-इंडिया के पक्ष में पट्टे दिए गए थे। बाद में, एसईसीएल के पक्ष में पट्टे जारी रहे और दिनांक 28/8/2015 तक वैध हैं।

5. संसद ने वनों के संरक्षण और आगे वनों की कटाई को रोकने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (एफसी अधिनियम) अधिनियमित किया। खनन गतिविधि एक गैर-वन गतिविधि है। यहां तक कि यदि एमएम अधिनियम के तहत किसी संस्था के पक्ष में खनन पट्टा है, तब भी एफसी अधिनियम के तहत केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन के बिना और राज्य सरकार द्वारा कब्जा सौंपे बिना वन क्षेत्र के भीतर खनन नहीं किया जा सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. वृक्ष हमारी जीवन रेखा हैं; क्योकि जहाँ वृक्ष वहाँ जीवन है हैं। यदि वृक्ष नहीं होते, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण हम निश्चित रूप से मर जाते। यही कारण है कि, यदि वन में गैर-वन गतिविधि करने के लिए एफसी अधिनियम के तहत पूर्व अनुमोदन है, तब भी वृक्षों को काटने के लिए वन अधिकारियों से अनुमति लेना आवश्यक है।

7. लेकिन वन क्या है? क्या यह केवल वही है जिसे सरकार द्वारा वन घोषित किया गया है या निजी भूमि पर भी वन हो सकता है? इस प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका, अर्थात् रिट याचिका (सी) संख्या 202, 1995 (टीएन गोदावरमन थिरुमुलकपाद बनाम भारत संघ और अन्य (गोदावरमन मामला)) में लिया था।

8. गोदावरमन मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न तिथियों पर आदेश पारित किए हैं। (1997) 2 एससीसी 267 में रिपोर्ट किए गए एक आदेश में, न्यायालय ने पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर दिया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

- एफसी अधिनियम को आगे वनों की कटाई की जांच करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः पारिस्थितिक असंतुलन होता है। इसे वनों के संरक्षण के लिए अधिनियमित किया गया है। इसे स्वामित्व या वर्गीकरण की प्रकृति के बावजूद सभी वनों पर लागू होना चाहिए;

- 'वन' शब्द को उसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए और एफसी अधिनियम की धारा 2 (1) के प्रयोजन के लिए सभी सांविधिक रूप से मान्यता प्राप्त वनों को शामिल किया जाना चाहिए, चाहे वे आरक्षित, संरक्षित या अन्यथा पदनामित हों;

- वन भूमि' शब्द, जो धारा 2 में आता है, न केवल शब्दकोश के अर्थ में 'वन' को शामिल करेगा, बल्कि स्वामित्व के बावजूद सरकारी अभिलेख में वन के रूप में दर्ज किसी भी क्षेत्र को भी शामिल करेगा;
- किसी भी 'वन' क्षेत्र के भीतर किसी भी गैर-वन गतिविधि के लिए केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है;
- जब तक केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन नहीं था, किसी भी राज्य में किसी भी वन के भीतर चल रही सभी गतिविधियां तत्काल बंद होनी चाहिए।

9. पूर्ववर्ती पैराग्राफ में दिए गए आदेश के अनुसरण में, अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने एफसी अधिनियम के अर्थ में 'वन' वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सभी कलेक्टरों को संबोधित एक पत्र संख्या 16/10/सात/2-ए/90 दिनांक 13/01/1997 जारी किया। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया था कि 10 हेक्टेयर या उससे अधिक के भूखंड को, जिसमें औसतन 200 पेड़ प्रति हेक्टेयर हों, वन माना जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. ऐसा प्रतीत होता है कि एसईसीएल आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बिना पेड़ काट रहा था। याचिकाकर्ता एक पत्रकार था और 1993 से अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न जिला अधिकारियों को शिकायतें कर रहा था। हालांकि, जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो उसने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष पहला रिट याचिका (WP) दायर किया। राज्य गठन के बाद इसे इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

प्रथम रिट याचिका दायर करने के बाद के तथ्य

11. प्रथम रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता ने दिनांक 6/9/2001 और दिनांक 23/4/2004 को नायब तहसीलदार के समक्ष विभिन्न आवेदन भी दायर किए। इन

आवेदनों पर कुछ रिपोर्टें प्रस्तुत की गईं। तत्पश्चात्, एस.डी.ओ. (राजस्व) ने राजस्व मामले संख्या 2/ए-62/2002-2003 और 3/ए-62/2002-2003 में दिनांक 22/7/2004 को, साथ ही राजस्व मामले संख्या 1/ए-62/2004-2005 में दिनांक 18/1/2005 को आदेश पारित किए, जिनके द्वारा एसईसीएल पर अवैध रूप से क्रमशः 289, 909 और 34 पेड़ काटने के लिए जुर्माना अधिरोपित किया गया।

12. एसईसीएल के पास दिनांक 30/4/2003 तक केंद्र सरकार से क्लीयरेंस था। इसके बाद, दिनांक 14/6/2004 को छह महीने की अवधि के लिए चिरमिरी वन क्षेत्र में काम करने के लिए एक नई अस्थायी कार्य अनुमति दी गई; यह दिनांक 13/12/2004 को समाप्त हो गई। तत्पश्चात्, दिनांक 13/6/2005 को फिर से 6 महीने के लिए एक अस्थायी कार्य अनुमति दी गई; यह भी दिनांक 12/12/2005 को समाप्त हो गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. एसईसीएल को दिनांक 12/12/2005 के बाद कोई अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि, एसईसीएल के अनुसार, उसने गोदावरमन मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 16/12/2005 के आदेश के अनुसरण में कार्य करना जारी रखा।

14. दिनांक 13/06/2005 की अस्थायी अनुमति में, एसईसीएल पर कुछ शर्तें लगाई गई थीं। एक शर्त यह थी कि कोई भी नया क्षेत्र नहीं तोड़ा जाएगा। इस पहलू पर विचार करते हुए, पहले रिट याचिका में दिनांक 9/8/2005 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि एसईसीएल कोई भी नया क्षेत्र नहीं तोड़ेगा और उस अनुमति में इंगित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का पालन करेगा।

15. पहली रिट याचिका विभिन्न तिथियों पर ली गई थी। हालांकि, दिनांक 20/2/2006 को इसे गोदावरमन मामले के निपटारे के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था।

16. एसईसीएल ने 15 जुलाई, 2011 को चिरमिरी क्षेत्र में 989.4 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन के लिए एफसी अधिनियम की धारा 2 के तहत केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त की। इसके बाद, एसईसीएल ने राज्य सरकार के समक्ष भूमि सौंपने के लिए एक आवेदन दायर किया, ताकि वह खनन कार्य शुरू कर सके।

17. याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के समक्ष एसईसीएल को वन भूमि सौंपने पर आपत्ति जताते हुए एक आवेदन दायर किया कि यदि भूमि एसईसीएल को सौंप दी जाती है, तो यह पहली रिट याचिका में पारित दिनांक 9/8/2005 के आदेश की अवमानना होगी।

18. एसईसीएल ने इस न्यायालय के समक्ष आदेश दिनांक 9/8/2005 के संशोधन/स्पष्टीकरण के लिए एक आवेदन (आईए संख्या 19) दायर किया। यह आदेश दिया गया था कि यह उपयुक्त पीठ के समक्ष आए, जिसमें वे न्यायाधीश शामिल थे जिन्होंने पहले आदेश पारित किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. मामला एक पीठ के समक्ष रखा गया जिसमें उन न्यायाधीशों में से एक शामिल था, जिन्होंने पहले आदेश पारित किया था। हालांकि, इस पीठ ने सोचा कि मामले को नियमित पीठ द्वारा निपटाया जाना चाहिए और इस प्रकार, मामले को पूर्ण पीठ के पास भेजा गया क्योंकि मतभेद था।

20. पूर्ण पीठ ने दिनांक 6/9/2012 के आदेश द्वारा, इस आधार पर प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर दिया कि उसे कोई प्रश्न नहीं भेजा गया था।

21. उपरोक्त प्रक्रिया में, समय बीत चुका था। एसईसीएल ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और 2 नवंबर, 2012 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया कि उच्च न्यायालय एसईसीएल द्वारा दायर आवेदन पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत

करने के 30 दिनों के भीतर निर्णय ले सकता है और यदि आवश्यक हो, तो एक विशेष पीठ का गठन किया जाए।

22. सर्वोच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 9/11/2012 को उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामला दिनांक 24/11/2012 को प्रशासनिक पक्ष में मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा गया, जिसमें एसईसीएल के अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि चूंकि एक बाहरी अधिवक्ता के पेश होने की संभावना है, इसलिए मामले को दिनांक 29/11/2012 को सूचीबद्ध किया जाए। मामले को दिनांक 29/11/2012 को मामले की सुनवाई करने वाली नियमित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आने का आदेश दिया गया।

23. दिनांक 29/11/2012 को, मामले को दिनांक 3/12/2012 को आने का आदेश दिया गया और पक्षकारो से अनुरोध किया गया कि वे एक तारीख चार्ट और निर्णयों की फोटोस्टेट प्रतियां प्रदान करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. दिनांक 3/12/2012 को, इसमें शामिल प्रश्नों के महत्व और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता स्वयं उपस्थित हो रहे थे:

- श्री गौतम भदुरी, श्री संजय के अग्रवाल, महाधिवक्ता (एजी), और सुश्री फौजिया मिर्जा, सहायक सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) से अनुरोध किया गया कि वे न्यायालय के मित्र के रूप में न्यायालय की सहायता करें; और[1]
- मामले को दिनांक 5/12/2012 के लिए सूचीबद्ध किया गया ताकि वे मामले की तैयारी कर सकें।

हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि मामले का अंतिम रूप से निर्णय किया जाएगा या कम से कम एसईसीएल द्वारा दायर आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा।

---

[1]1 श्री संजय के अग्रवाल (एजी), सुश्री फौजिया मिर्जा (एएसजी), और श्री गौतम भदुरी मामले में न्यायालय के मित्र के रूप में उपस्थित हुए हैं। वे विधिक सहायता समिति से एक मामले के लिए शुल्क के हकदार होंगे।

तथ्य - दूसरा रिट याचिका

25. प्रथम रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, एसईसीएल ने अपनी आवासीय कॉलोनी में खड़े पेड़ों को काटने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया। पेड़ों को काटने की अनुमति दिनांक 10/6/2009 को दी गई थी।

26. याचिकाकर्ता ने दिनांक 10/6/2009 को दी गई अनुमति के खिलाफ अपनी आपत्ति दायर की। जब तक आपत्ति सुनवाई के लिए आई, तब तक एसईसीएल द्वारा कुछ पेड़ काट दिए गए थे और केवल 63 पेड़ बचे थे।

27. अतिरिक्त कलेक्टर, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया ने दिनांक 22/8/2009 को याचिकाकर्ता की आपत्ति को खारिज कर दिया और एसईसीएल को शेष पेड़ों को काटने की अनुमति दी। याचिकाकर्ता ने इस आदेश के खिलाफ दूसरी रिट याचिका दायर की है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

28. हमने याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुना; श्री जगदीप धनखड़, ग्रुप कैप्टन श्री करण सिंह भाट और श्री आरके गुप्ता एसईसीएल के लिए; एजी, एएसजी, और श्री गौतम भादुड़ी, न्यायालय के मित्र के रूप में। एजी और एएसजी ने राज्य और भारत संघ का भी प्रतिनिधित्व किया। पक्षकारो की सहमति से, दोनों रिट याचिकाओं पर अंतिम रूप से निर्णय लिया जा रहा है।

निर्णय - पहला डब्ल्यूपी

29. पूर्ववर्ती शीर्षक 'तथ्य' में बताए गए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि कुछ समय के लिए, एसईसीएल के पास वन क्षेत्र में काम करने के लिए न तो कोई मंजूरी थी, न ही कोई अनुमति या सर्वोच्च न्यायालय का कोई आदेश था। फिर भी, एसईसीएल ने न केवल जंगल के अंदर गैर-वन गतिविधि की, बल्कि बिना किसी अनुमति के पेड़ भी काट डाले, जिसके लिए उस पर जुर्माना भी लगाया गया।

30. मामले का अभिलेख यह भी दर्शाता है कि कार्रवाई करने में राज्य सरकार की ओर से उदासीनता थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। भले ही एसईसीएल जनहित के लिए कोयला खनन कर रहा हो, अनधिकृत साधन अनुमेय नहीं हैं। किसी को गांधी के दर्शन को याद रखना चाहिए:

> 'साधन अंत से अधिक महत्वपूर्ण हैं: यह केवल सही साधनों से ही है कि वांछित अंत प्राप्त होगा।'

31. यह न केवल हमारा दर्शन है, बल्कि अन्य राष्ट्रों का कानून भी है। आर बनाम इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर और अन्य, एक्स पार्टे रॉसमिनस्टर लिमिटेड और अन्य प्रतिवेदित है। 3 ऑल ईआर 385 में:

> 'लेकिन हमारा यह मुलभुत कानून है कि जो साधन अपनाए जाते हैं वे वैध साधन होने चाहिए। एक अच्छा अंत बुरे साधन को उचित नहीं ठहराता है।'

केवल इसलिए कि एसईसीएल एक सरकारी कंपनी है, इसका अन्य यह नहीं है कि उसके पास कानून का उल्लंघन करने का लाइसेंस है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. विधि का पालन करना चाहिए, यहां तक कि एक शैतान भी अपनी सुरक्षा का हकदार है: 'ए मैन फॉर ऑल सीजन्स' एक्ट I पेज १४७ में बोल्स को याद रखना चाहिए, जिसे यूएस सुप्रीम कोर्ट ने टेनेसी वैली अथॉरिटी बनाम हिरम जी. हिल ४३७ यूएस १५३, ५७ एल.एड २nd ११७ = ९८ एस सीटी २२७९ में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया था:

> 'विधि, रोपर, विधि मैं जानता हूँ कि क्या वैध है, क्या सही नहीं और जो वैध है, उसी पर टिका रहूँगा... मैं ईश्वर नहीं हूँ। सही और गलत के वे प्रवाह और भंवर, जिन्हें आप इतना सीधा-सादा समझते हैं, मैं उनमें नहीं चल सकता, मैं

कोई नाविक नहीं हूँ। लेकिन विधि के घने जंगलों में, ओह, वहाँ मैं एक वनपाल हूँ.... आप क्या करेंगे? शैतान का पीछा करने के लिए विधि के बीच से एक बड़ा रास्ता काटेंगे। और जब अंतिम विधि भी खत्म हो जाएगी और शैतान आपकी ओर मुड़ेगा, तो आप कहाँ छिपेंगे, रोपर, जब सभी विधियाँ समतल हो जाएँगी.... यह देश तट से तट तक विधियों से भरा हुआ है - मनुष्य की विधि और ईश्वर की विधि - और यदि आप उन्हें काट देते हैं... क्या आप सचमुच सोचते हैं कि तब चलने वाली हवाओं में आप सीधे खड़े रह पाएंगे... हाँ, मैं अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए शैतान को भी विधि का लाभ दूँगा।'

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पर्यावरण, पेड़ शैतान नहीं हैं; वे कहीं बेहतर सुरक्षा के हकदार हैं: आखिरकार, हमने उन्हें अपने बच्चों से उधार लिया है और उन्हें वापस लौटाने का वचन दिया है, यदि बेहतर स्थिति में नहीं, तो कम से कम उसी स्थिति में, जिसमें हमने उन्हें प्राप्त किया था।

33. याचिकाकर्ता, एक अच्छे नागरिक के रूप में, शिकायतें कर रहा था। यह केवल तब हुआ जब राज्य के अधिकारियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तब पहली रिट याचिका (WP) दायर की गई। तब भी, केवल एक नायब तहसीलदार, एक छोटे अधिकारी ने, एसईसीएल द्वारा अवैध रूप से पेड़ काटने के बारे में एक रिपोर्ट बनाने का साहस किया।

34. एसईसीएल के अधिवक्ता का यह निवेदन है कि:

- पेड़ों के अवैध कटान के लिए जुर्माना अधिरोपित किया गया था;
- इसे जमा कर दिया गया है; और
- यह मामला समाप्त होना चाहिए।

35. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सरकारी कंपनी को ऐसा सोचना या प्रस्तुत करना चाहिए। पेड़ों की कटाई कोई सामान्य क्षति नहीं है जिसकी भरपाई पैसे के रूप में की जा सके। जुर्माना भरना पेड़ों की कटाई के लिए बहुत कम कीमत है और वह भी किसी सामान्य कंपनी द्वारा नहीं बल्कि एक सरकारी कंपनी द्वारा।

36. सभी से कानून का पालन करने की अपेक्षा की जाती है; विशेष रूप से एसईसीएल से; इसे एक आदर्श कंपनी होना चाहिए: यह अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। हालांकि, यह अतीत की बात है, फिर भी हम बाद में इसका उल्लेख करेंगे।

37. एसईसीएल को दिनांक 24/4/2006 को कुछ शर्तों के पूरा होने के अधीन सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई थी। राज्य सरकार ने तब सैद्धांतिक मंजूरी में निर्धारित शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और केंद्र सरकार से अंतिम मंजूरी देने का अनुरोध किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

38. राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर, एफसी अधिनियम की धारा 2 के तहत दिनांक 15/7/2011 को अंतिम मंजूरी दी गई थी। यह उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन है:

- शर्त संख्या 8 के तहत, अनुमति एमएम अधिनियम के तहत दी गई खनन पट्टे के साथ या 20 साल के लिए, जो भी कम हो, सह-समाप्ति होगी;
- शर्त संख्या 17 के तहत, एसईसीएल को शर्तों के अनुपालन की स्व-निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी;
- शर्त संख्या 20 के तहत, मुख्य वन संरक्षक (केंद्रीय) क्षेत्रीय अधिकारी, भोपाल (सीसीएफ-भोपाल) संरक्षण, सुरक्षा या वनों के विकास के हित में शर्तें अधिरोपित कर सकते हैं।

39. एसईसीएल के पिछले आचरण और अधिकारियों की उदासीनता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार और सी.सी.एफ.-भोपाल निम्नलिखित कर सकते हैं:

- एसईसीएल द्वारा काटे गए प्रत्येक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाने की शर्त अधिरोपित कर सकते हैं और भविष्य में भी ऐसा ही करने के लिए कह सकते हैं;
- शर्त 17 के तहत स्व-विनियमन के अलावा, यह देखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी समिति का प्रावधान कर सकते हैं कि क्या 15.7.2011 को दी गई मंजूरी में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं;
- याचिकाकर्ता को अन्य व्यक्तियों के साथ स्वतंत्र समिति में से एक व्यक्ति के रूप में नामित कर सकते हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

यह जोड़ना की आवश्यकता नहीं है कि यदि एसईसीएल को कब्जा सौंप दिया जाता है, तो राज्य सरकार और सी.सी.एफ.-भोपाल कोई भी अन्य शर्त अधिरोपित कर सकते हैं जो वे उचित समझें।

40. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता या कोई अन्य इच्छुक व्यक्ति राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत दिनांक 15/7/2011 को दी गई मंजूरी की वैधता पर प्रश्न उठा सकता है।

निर्णय - दूसरा रिट याचिका

41. दूसरे रिट याचिका में, दिनांक 22/8/2009 के आदेश को चुनौती दी गई है। इस आदेश द्वारा पेड़ों को काटने के लिए एसईसीएल को दी गई अनुमति के विरुद्ध याचिकाकर्ता की आपत्ति को खारिज कर दिया गया है। पेड़ों को काटने की अनुमति और आपत्तियों को खारिज करने का आदेश छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (संहिता) की धारा 240 के तहत पारित किया गया था। यह संहिता की धारा 44 के तहत अपील योग्य है और फिर धारा 50 के तहत पुनरीक्षण योग्य है।

42. याचिकाकर्ता, यदि वह चाहे, तो उसी के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है। उसके लिए अपील दायर करने में हुई देरी को माफ करने के लिए आवेदन दाखिल करना भी संभव होगा।

निष्कर्ष

43. हमारे निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

(क) एसईसीएल के पिछले आचरण और अधिकारियों की उदासीनता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार और सीसीएफ-भोपाल निम्न कर सकते हैं:

- एसईसीएल द्वारा काटे गए प्रत्येक पेड़ के लिए और भविष्य में काटे जाने वाले पेड़ों के लिए 10 पेड़ लगाने की शर्त अधिरोपित करें;
- दिनांक 15/7/2011 के अनुमोदन की शर्त 17 के तहत स्व-विनियमन के अलावा, यह देखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी समिति का प्रावधान करें कि अनुमोदन में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं;
- याचिकाकर्ता को अन्य व्यक्तियों के साथ स्वतंत्र समिति में से एक व्यक्ति के रूप में नामित करें।

यह जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि यदि एसईसीएल को कब्जा सौंप दिया जाता है तो राज्य सरकार और सीसीएफ, भोपाल कोई अन्य शर्त अधिरोपित कर सकते हैं जिसे वे उचित समझें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ख) एसईसीएल को 15.7.2011 को अनुमोदन प्रदान किया गया था। याचिकाकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति, यदि उन्हें ऐसा परामर्श दिया जाता है, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत अनुमोदन को चुनौती दे सकते हैं;

(ग) याचिकाकर्ता, यदि वह चाहे, तो दिनांक 22.08.2009 के आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है।

44. हमारे निष्कर्ष के आलोक में:

- प्रथम रिट याचिका (रिट याचिका संख्या 4520, 2000) टिप्पणियों के साथ निपटाई जाती है;
- द्वितीय रिट याचिका (रिट याचिका (सी) संख्या 5354, 2009) टिप्पणियों के साथ खारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/- हस्ताक्षरित/-

मुख्य न्यायाधीश सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By ...... Pritika Pandya